

संपादक की कलम से

केजरीवाल को जमानत मामले में प्रवर्तन निदेशालय की सफलता क्षणिक

कंजरीवाल लगातार कहते रहे हैं कि ईडी उनके खिलाफ़ कोई विश्वसनीय सुबूत पेश करने में विफल रही। न्यायालय की टिप्पणियों के बाद इस बिंदु पर उनका जोर विश्वसनीयता प्राप्त करता है। यदि ईडी के पास वास्तव में युखा सुबूत नहीं हैं, तो यह एजेंसी के मामले पर सवाल उठाता है। हालांकि ईडी ने कंजरीवाल की जमानत पर स्थगन प्राप्त करने में कानूनी पैंतेरेबाजी की है, लेकिन मामले के मूल पहलू अभी भी अनसुलझे हैं।

वरवर्ती निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा कर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के जमानत पर बाहर आने के जश्न में बाधा डालने में कामयाबी हासिल की है, जबकि न्यायालय के आदेश पर वह अपना हाथ भी नहीं डाल सकता था। फिर उच्च न्यायालय ने कुछ ग्रक्षियागत मुद्दों के आधार पर इस पर अस्थायी रोक लगा दी है। लेकिन यह उसकी कोई बड़ी जीत नहीं हो सकती है, क्योंकि यह रोक केवल तब तक तागू रहेगी, जब तक कि ईडी की चुनौती पर सुनवाई नहीं हो जाती और न्यायालय द्वारा अगले 2-3 दिनों में इसका निपटाग नहीं कर दिया जाता।

जिस तरह से ईडी ने प्राकृतिक न्याय को अवरुद्ध करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहाई में देरी करने के लिए काम किया है, उसकी व्यापक निंदा हुई है। बड़ा सवाल यह है कि प्रक्रियात्मक मुद्दों का सहारा लेकर एजेंसी अपनी विफलताओं को किस हद तक छिपा सकती है और जब अदालत मूल मुद्दों और ईडी की आपत्तियों के गुण-दोष पर विचार करेगी, खासकर उस संदर्भ में जब मूल अदालत ने मामले के बारे में गंभीर संसदीय व्यक्त करते हुए जमानत दी थी। ईडी की केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत पर स्थगन प्राप्त करने में सफलता मुख्य रूप से तकनीकी आधार पर थी न कि केजरीवाल के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता पर। एजेंसी ने तर्क दिया कि उसे जमानत की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन करने का पर्याप्त अवसर पहंच दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा इस तर्क को स्वीकार करना ईडी के लिए एक ठोस जीत के बजाय एक प्रक्रियात्मक जीत का संकेत देता है। उससे केजरीवाल के खिलाफ ईडी के मामले की मजबूती पर सवाल उठते ही हैं। प्रारंभिक जमानत कार्रवाई के दौरान सुबूतों के माध्यम से केजरीवाल की संपत्तियां एकत्र किये गये सुबूतों में कमजोरियों का संकेत दे सकती है। वास्तव में, राउज एवेन्यू कोर्ट के जज द्वारा दिये गये 25-पृष्ठ के आदेश में ईडी के तौर-उत्तरीके की गंभीर आलोचना की गई है, जिसमें अपर्याप्त सुबूत प्रस्तुत करना और कथित मनी लॉन्डिंग मामले की जांच में संभावित पक्षपात दिखाना शामिल है। जबकि मनी लॉन्डिंग की पुष्टि हो गई है, एजेंसी केजरीवाल को नेन-देन से जोड़ने में विफल रही है।

कोर्ट ने बिना किसी पुष्ट सुबूत के सह-आरेपी और अनुमोदकों के बयानों पर भरोसा करने के लिए ईडी की भी आलोचना की। अदालत की टिप्पणी वर्तमान राजनीति की एक दर्दनाक सच्चाई की ओर इशारा करती है, जब उसके आदेश में कहा गया है-'अदालत को इस तर्क पर विचार करने के लिए रुकना होगा, जो कि एक स्वीकार्य दलील नहीं है कि जांच एक कलालैनरी है, क्योंकि अगर ऐसा है, तो किसी भी व्यक्ति को फंसाया जा सकता है और उसके रखँड़ से दोषमुक्ति सामग्री को कलात्मक रूप से हटाने के बाद उसके खिलाफ सामग्री को कलात्मक रूप से हासिल करके सलाखों के पीछे रखा जा सकता है।' जांच प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों की धारा 45 के अनुचित अधिक भरोसा किया, जो प्रक्रियात्मक तकनीकी की मदद से कानूनी निष्पक्षता और निर्दोषता के अनुमान के सिद्धांतों को प्रभावित करता है।' अदालत ने आगे कहा कि केजरीवाल को अदालत पर लिए तब नहीं किया था, लेकिन ईडी के चल रहे जांच दावे के आधार पर वह अपनी भी न्यायिक हिंगात में है। प्रक्रियाओं पर यह अनुचित दबाव ईडी के मामले को और कमजोर करता है। राहत के लिए उच्च न्यायालय का समन आये मूल मुद्दों को नहीं उठा रहे थे, बल्कि सुनवाई की प्रक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे। एजेंसी के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एसएसजी) एसवी राजू ने उच्च न्यायालय से शिकायत की कि उन्हें अपना मामला रखने का 'पूरा अवसर' नहीं दिया गया और यहां तक कि उन्होंने न्यायाधीश के आदेश को 'विकृत' करार दिया। केजरीवाल लगातार कहते ही हैं कि ईडी उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय सुबूत पेश करने में विफल रही है। न्यायालय की टिप्पणियों के बाद इस बिंदु पर उनका जोर विश्वसनीयता मामला करता है। यदि ईडी के पास वास्तव में पुछता सुबूत नहीं है, तो यह एजेंसी के मामले पर सवाल उठाता है। हालांकि ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर स्थगन प्राप्त करने में कानूनी पैतरेबाजी की है, लेकिन मामले के अन्त मामले अपनी भी विवादों से हैं।

18वीं लोकसभा : दक्षिणात्र से पार्कआत

18वीं लोकसभा : टकराव से शुरूआत

जोट-यूजी की परीक्षा को लेकर उठे बवाल के उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। विशेष भर में मेडिकल कालेजों में दाखिले की इस परीक्षा में इस बार इतनी ज्यादा और अधिक तने खुले तौर पर गडबडिया हुई है कि, मैन स्ट्रीम मीडिया पर मोदी राज के सारे नियत्रण और विवरण बाबूद, इन धांषिलयों के खिलाफ खत्म स्फूर्त आंदोलन को तो जी से बढ़ने से रोका जाए हीं जा सका है।

पठरहरवीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत से ऐन पहले, अपने परंपरागत वक्तव्य के अनुसार विप्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनकी सरकार से, जनादेश का विवरण बादर करते हुए, पहली पारियों के मुकाबले, तौर-तरीकों में किसी खास बदलाव की विवरण नहीं की जानी चाहिए। बैशक, प्रधानमंत्री ने संसद ही नहीं, आमतौर पर शासन के लिए भी बहुमत से बढ़कर, आम सहमति के जरूरी होने पर विश्वास करने का दावा किया। लेकिन, इसके पीछे इस बार के जनादेश से उत्पन्न किसी विनम्रता की जगह, विवरण सर्फ बयानबाजी थी और यह प्रधानमंत्री के इसके दावे से साफ नजर आता था कि उनकी सरकार तो, दस साल से आम सहमति बनाने और सब को साथ लेकर चलने के ही लिए आरते पर चल रही थी! बची-खुकी करार, प्रधानमंत्री द्वारा इस मोके पर भी छोड़े गए।

विवेषक्ष के खिलाफ इस प्रकार के तीरों ने पूरी कर दी कि लोग संसद से बहस की अपेक्षा नहीं हुआ तो वह, एक दिन बाद झमज़सी लगाए जाने का पचासवां साल शुरू होने के बाद से, विस्तर से झमज़सी को विकारने में चले गए, जिसका मकसद सबसे बढ़कर हाल हाल साबित करना था कि उनके राज के दस साल में संविधान पर आया संकट तो, कोई संकट ही नहीं था। हैरानी की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ने अपने इस वक्तव्य से इसी कारण शारा दिया है कि संसद के पिछले कई सत्रों की तरह, अटारहवीं लोकसभा का पहला

मत्र भी तीखे टकराव का ही सब होने जा रहा है मोदी और उनकी भाजपा, जिस तरह वे इस चुनाव के जनादेश को तोड़ने-मरोड़ने और उसके कई महत्वपूर्ण तत्वों को बदलने की ही काशिश कर रहे हैं, उसे देखते हुए एक बार फिर यह याद दिलाना अनुप्युत नहीं होगा कि अगर, आने एनडीए गठबंधन के 293 के आंकड़े के बल पर, नरेंद्र मोदी के नतुर में तीसरी बार सरकार बनना, 2024 के जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो उसी जनादेश का इतनी ही महत्वपूर्ण पहलू कुल मिलाकर देश की जनता द्वारा मोदी की भाजपा का हरेक पहलू से दुकराया जाना है। 2019 के चुनाव के मुकाबले खुद भजपा की सीटें 303 से घटकर 240 पर आ जाना और पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें लड़ने वालजूद, उसका अपना मत फीसद करीब 1 फीसद घट जाना और इसी प्रकार, मोदी के नेतृत्व में चल रहे एनडीए की सीटें, साठे तीन सौ से ऊपर से घटकर 293 रह जाना और उसके मत फीसद में भाजपा से भी ज्यादा गिरावट होना, उसी जनादेश के महत्वपूर्ण अंकेत हैं। जनादेश के दोनों पहलुओं का जोड़कर देखें तो, सक्षम प्रयोग में इस बार का चुनावी नतानादेश देश में केंद्रीय सत्ता, मोदी और उनकी भाजपा के हाथों से छीनकर, एक साफ़ प्रयोग पर उससे कई व्यापक गठबंधन को सौंपेंगे का जनादेश है।

वायु प्रदूषण से होती लाखों मौतों के लिये कौन जिम्मेदार ?

-ललित गर्ग-

कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन भारत में बढ़ते प्रदूषण के कारण जान और जहान दोनों ही खतरे में हैं। देश की हवा में घुलते प्रदूषण का ह्यजहरल अनेक बार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाना चिन्ता का बड़ा कारण है। प्रदूषण की अनेक बोंदियाँ एवं हिदयतां के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण की बात खोखली साबित हो रही है। यह कैसा समाज है जहां व्यक्ति के लिए पर्यावरण, अपना स्वास्थ्य या दूसरों की सुविधा-असुविधा का कोई अर्थ नहीं है। जीवन-शैली ऐसी बन गयी है कि आदमी जीने के लिये सब कुछ करने लगा पर खुद जीने का अर्थ ही भूल गया, इस गंभीर होती स्थिति को यूनिसेफ और अमेरिका के स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान ह्यहेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट्ह की साझेदारी में जारी रिपोर्ट ने बयां किया है, इस रिपोर्ट के आंकड़े परेशान एवं शर्मसार करने के साथ चिन्ता में डालने वाले हैं, जिसमें वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से 21 लाख भारतीयों के मरने की बात कही गई है। ज्यादा दुख की बात यह है कि मरने वालों में 1.69 लाख बच्चे हैं, जिन्होंने अभी दुनिया ठीक से देखी ही नहीं थी। निश्चय ही ये आंकड़े जहां व्यक्ति, चिन्तीत व परेशान करने वाले हैं। वही सरकार के नीति-नियंताओं के लिये यह शर्म का विषय होना चाहिए, लेकिन उन्हें शर्म आती ही कहा है? तानिक भी शर्म आती तो सरकारें एवं उनके कर्ता-धर्ता इस दिशा में गंभीर प्रयास करते सरकार की नाकामियां ही हैं कि जिन्दगी विषमताओं और विसंगतियों से घिरी होकर उसे कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है।

जानलेवा वायु प्रदूषण न केवल भारत के लिये बल्कि दुनिया के लिये एक गंभीर समस्या है। चीन में

मोदी का रवैया न

18वीं लोकसभा के विशेष सत्र के समक्ष उद्घान करते हुए प्रधानमंत्री ने है कि वे अपने पूर्ववर्ती रवैये को ब 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र नहीं करेंगे। इसके साथ यह भी सालडाइ के लिये तैयार रहना है। आसत्तारु भारतीय जनता पार्टी व एलायंस (एनडीए) के मुकाबले होकर लोकसभा में पहुंचा है। सोमवार दिलाने की कार्रवाई शुरू हुई जो मराठपति द्वापदी मुर्मू दानों सदनों (सम्बोधित करेंगी। बाद में उनके अपने मोदी ने जो बातें राष्ट्र के समाने रखीं ही नजर आया क्योंकि उनका 370 अपने चुनावी प्रचार के दौरान मोदी व भाजपा के बूते 370 तथा एनडीए अधिक होने की बात कर रहे थे। सिमट गई और उसे तेलुगु देशम पर सरकार बनानी पड़ी है। इस निराश शुरूआत 25 जून, 1974 में तत्काल गए आपातकाल से की। भारतीय इन्डिया को अपने राजनीतिक फायदे के लिये इसीलिये निष्पात माने जाते हैं कि नेकटकर जनता के समक्ष परोसने सकारात्मक नोट से करनी चाहिये उन्होंने वही राह पकड़ी जिस पर वे मोदी की वाराणसी से तीसरी बार जीघटा है। यहां तक कि मतदान के प्रथे। अपनी इस नैतिक पराजय को प्रस्तुत करते मोदी ने विपक्ष को जो आप में हास्यास्पद है। अपने पिछले निरंकुश तरीके से सरकार चलाई, उकोई सरकार तानाशाही लागू करने कि 'सांसदों से देश को बहुत अपेक्षा के लिये इस अवसर का उपयोग कर जरूरत बतलाते हुए मोदी ने कहा फिर व्यवधान नहीं बल्कि चर्चा और मेहनत पूछे जाने व नारेबाजी को 'इमें' की संसद चाहते हैं जो उनसे प्रश्न न करें लम्बे समय तक विपक्ष की भूमिका है कि मोदी को लोकतंत्र में प्रतिरोध प्रतिपक्ष का सम्मान करना जानते हैं हमेशा की तरह मोदी की कथनी और मोदी पिछली दो सरकारों में चचाऊं सरकार से पूछे जाने वाले सवालों विवादास्पद विषय पर उन्होंने न तो तथ्यात्मक जानकारी संसद के अंतर्गत



भा इसा कालखड़ म 23 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरे हैं। जहाँ तक पूरी दुनिया में इस वर्ष मरने वालों की कुल संख्या का प्रश्न है तो यह करीब 81 लाख बतायी जाती है। चिंता की बात यह है कि भारत व चीन में वायु प्रदूषण से मरने वालों की कुल संख्या के मामले में यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 54 फीसदी है। जो हमारे तंत्र की विफलता, गरीबी और प्रदूषण नियंत्रण में शासन-प्रशासन की कोताही एवं लापरवाही को ही दर्शाता है। इसमें आम आदमी की लापरवाही भी कम नहीं है। आम आदमी को पता ही नहीं होता है कि किन प्रमुख कारणों से वह प्रदूषण फैला रहा है और किस तरह वे इस जानलेवा प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहयोगी हो सकते हैं। प्रश्न है कि आम आदमी एवं उसकी जीवनशैली वायु प्रदूषण को इतना बेपरवाह होकर क्यों फैलाती है? क्यों आदमी मृत्यु से नहीं डर रहा है? क्यों भयभीत नहीं है? देश की जनता दुख, दर्द और संवेदनहीनता के जटिल दौर से रूबरू है, प्रदूषण जैसी समस्याएं नये-नये मुख्यों

आढ़कर डराता ह, भयभात करता है। विडम्बना तो यह है कि विभिन्न राज्यों की सरकारें इस विकट होती समस्या का हल निकालने की बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करती है, जानबूझकर प्रदूषण फैलाती है ताकि एक-दूसरे की छीछालेदार कर सके। प्रदूषण के नाम पर भी कोरी राजनीति का होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

दिल्ली सहित उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का बेहद खतरनाक स्थिति में बना रहना चिन्ता में डालता है। हालत ये बनते हैं कि कभी-कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लोगों को धरों में ही रहने को मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में प्रदूषण का बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं होता है। पराली के बाद पटाखों का धुआं भी बड़ी समस्या है, इसके अलावा सड़कों पर लगातार बढ़ते निजी वाहन, गुणवत्ता के इंधन का उपयोग न होना, निर्माण कार्य खुले मैं होना, उद्योगों की घातक गैसों व धुएं का

नियमन न हान एव बढ़ता ध्रुवपान
जैसे अनेक कारण वायु प्रदूषण
बढ़ाने वाले हैं। वर्ही दूसरी ओर
आवासीय कॉलोनियों व
व्यावसायिक संस्थानों का
विज्ञानसम्मत ढंग से निर्माण न हो
पाना भी प्रदूषण बढ़ाने की एक
बजह है। यह कैसी शासन-
व्यवस्था है? यह कैसा अदालतों
की अवमानना का मामला है? यह
सभ्यता की निचली सीढ़ी है, जहाँ
तनाव-ठहराव की स्थितियों के
बीच हर व्यक्ति, शासन-प्रशासन
प्रदूषण नियंत्रण के अपने दायित्वों
से दूर होता जा रहा है।
यूनीसफ की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण
से 1 लाख 69 हजार बच्चे
जिनकी औसत आयु पांच साल से
कम बतायी गई है, मौत के शिकायत
होते हैं। जानलेवा प्रदूषण का
प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर होने से
बच्चे समय से पहले जन्म ले
लेते हैं, इनका समुचित शारीरिक
विकास सही ढंग से नहीं हो पाता।
इससे बच्चों का कम वजन का
पैदा होना, अस्थमा तथा फेफड़े
की बीमारियां से पीड़ित होना हैं
हमारे लिये चिंता की बात यह है

कि बेहद गरीब मुल्कों नाहजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथोपिया से ज्यादा बच्चे हमारे देश में वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। दिल्लीना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के संकट ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या को बढ़ाया ही है। एक अरब चालीस करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत के लिये यह संकट बहुत बड़ा है। दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में प्रदूषण जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। हर कुछ समय बाद अलग-अलग बजहों से हवा की गुणवत्ता का स्तर हाँबेहद खराबह की श्रेणी में दर्ज किया जाता है और सरकार की ओर से इस स्थिति में सुधार के लिए कई तरह के उपाय करने की घोषणा की जाती है। हो सकता है कि ऐसा होता भी हो, लैकिन सच यह है कि फिर कुछ समय बाद प्रदूषण का स्तर गहराने के साथ यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसकी असली जड़ क्या है और क्या सरकार की कोशिशें सही दिशा में हो पा रही हैं? इस विकट समस्या से मुक्ति के लिये ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहर वायु प्रदूषण की गंभीर मार झेलते हैं। इसका पता तब ज्यादा चलता है जब वैश्विक पर्यावरण संस्थान अपने वायु प्रदूषण सूचकांक में शहरों की स्थिति को बताते हैं। पिछले कई सालों से दुनिया के पहले बीस प्रदूषित शहरों में भारत के कई शहर दर्ज होते रहे हैं। जाहिर है, हम वायु प्रदूषण के दिनांदिन मर्दाने गंभीर से चिप्पा पाने में जो तंबाकू सेवन से होने वाली मौतें का नंबर आता है। दरअसल गरीबी और अर्थिक असमानता के चलते बड़ी आबादी बेन केन प्रकारेण जीविका उपार्जन में लग्न रहती है, उसकी प्राथमिकता प्रदूषण से बचाव के बजाय रोटी ही है। वहीं दुलमुल कानूनों, तत्र कर्म काहिली तथा जागरूकता के अभाव में वायु प्रदूषण रोकने की गंभीर पहल नहीं हो पाती। मुश्किल यह है कि वायुमंडल के धनीभूत होने की वजह से जमीन से उठने वाली धूल, पराली की धूंध और वाहनों से निकलने वाले धुएं के छंटने की गुंजाइश नहीं बन पारत है। नतीजन, वायु में सूक्ष्म जहरीले तत्व घुलने लगते हैं और प्रदूषण के गहराने की दृष्टि से इसे खतरनाक माना जाता है। हमारा राष्ट्र एवं दिल्ली सहित अन्य राज्यों की सरकारें नैतिक, आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक एवं व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में मनोबल के दिवालिएन के कागर पर खड़ी हैं और हमारा नेतृत्व गौरवशाली परम्परा, विकास और हर प्रदूषण खतरों से मुकाबला करने के लिए तैयार है, का नारा देकर अपनी नेकनीयत का बखान करते रहते हैं। पर उनकी नेकनीयती की वास्तविकता किसी से भी छिप्पी नहीं है, देश में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के आंकड़े इस वास्तविकता को उजागर करते हुए प्रदूषण की समस्या का काइ दीर्घकालिक और ठोस हल निकालने के लिये चेता रहे हैं।

प्रेषक: (ललित गर्ग)
 लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
 ई-253, सरस्वती कुंज
 अपार्टमेंट
 25 आई० पी० एक्सटेंशन
 पटपड़गंज, दिल्ली-92
फोन: 22727486

मोदी का रवैया न बदलने के संकेत

18वीं लोकसभा के विशेष सत्र की शुरूआत होने के पहले मीडिया समक्ष उद्घोषण करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो कुछ कहा, उससे साधा है कि वे अपने पूर्ववर्ती रवेंगे को बरकरार रखेंगे। विपक्ष को कोसने तक 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने जैसे सब्जिबाग दिखाना वे बहुत नहीं करेंगे। इसके साथ यह भी साफ हो गया है कि विपक्ष को एक बड़ा लड़ाई के लिये तैयार रहना है। आशा इस बात से बंधती है कि इस बड़ी सत्तारूढ़ी भारतीय जनता पार्टी व उसके गठबन्धन नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) के मुकाबले संयुक्त प्रतिपक्ष इंडिया काफी मजबूत होकर लोकसभा में पहुंचा है। सोमवार को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की कारवाई शुरू हुई जो मांगलवार तक जारी रहेगी। बुधवार विपक्ष राष्ट्रपति द्वारा पदी मुर्ख दोनों सदनों (राजसभा के साथ) के सदस्यों व प्रारंभिक बर्तीमी तक में उसके अधिकाराओं पर जर्नली देंगे।

सम्बाधित करना। बाद में उनका आभिभावण पर चंचा होगा। मोदी ने जो बातें राष्ट्र के सामने खेंगी उनसे सर्वप्रथम तो उनका पराजय भ ही नजर आया क्योंकि उनका 370 व 400 पार का नारा विफल रह अपने चुनावी प्रचार के दौरान मोदी व भाजपा के सारे स्टार प्रचारक अकेभाजपा के बूते 370 तथा एनडीए की सम्पालित शक्ति 400 सदस्यों अधिक होने की बात कर रहे थे। ऐसा तो नहीं हुआ, भाजपा 240 सिमट गई और उसे तेलुगु देशम पार्टी व जनता दल यूनाइटेड के सह

सरकार बनानी पड़ी है। इस निराशा के चलते मोदी ने अपने भाषण व सुरुआत 25 जून, 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल से की। भारतीय इतिहास की कटु व विषादपूर्ण घटनाएँ को अपने राजनीतिक फायदे के लिये उछालने वाले मोदी इस कला-इस्सीलिये निष्पात माने जाते हैं कि वे उन्हें तोड़-मरोड़कर और सन्दर्भों काटकर जनता के समझ परोसते हैं। इस सत्र की शुरुआत उसकारात्मक नोट से करनी चाहिये थी, लेकिन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने वही राह पकड़ी जिस पर वे पिछले दस वर्षों से चलते आये हैं। मोदी की वाराणसी से तीसरी बार जीत में पहले दो के मुकाबले अंतर का घटा है। यहां तक कि मतदान के प्रथम दो-तीन चक्रों में वे पिछड़ भी चुना थे। अपनी इस नैतिक पराजय को भी किसी महान विश्वविजय की तरह प्रस्तुत करते मोदी ने विषक्ष को जो पाठ पढ़ाने की कोशिश की वह अपार में हास्यास्पद है। अपने पिछले दो कार्यकालों में जिन मोदी ने बेतामनिरुक्षा तरीके से सरकार चलाई, उनका यह दावा था कि 'अब कभी कोई सरकार तानाशाही लागू करने की नहीं सोचेगा'। उन्होंने यह भी कहा कि 'सांसदों से देश को बहुत अपेक्षाएँ हैं अतः उन्हें जनहित व लोकसेवा के लिये इस अवसर का उपयोग करना चाहिये।' एक जिम्मेदार विषक्ष द्वारा जरूरत बतलाते हुए मोदी ने कहा कि 'लोग नारे नहीं सार्थकता चाहते व्यवधान नहीं बल्कि चर्चा और मेहनत चाहते हैं।' उन्होंने विषक्ष के सवाल पूछे जाने व नरेबाजी को 'ड्रामे' की संज्ञा दी, जो बतलाता है कि मोदी ऐसे संसद चाहते हैं जो उनसे प्रश्न न करे। मोदी उसी भाजपा से आते हैं जिस लम्बे समय तक विषक्ष की भूमिका निभाई है। उनका यह बयान बतलाता है कि मोदी को लोकतंत्र में प्रतिरोध का न तो महत्व ज्ञात है और न ही प्रतिष्पक्ष का सम्मान करना जानते हैं।

हमेशा की तरह मोदी की कथनी और करनी का अंतर साफ दिखा कि स्व-सेवी विषक्ष ने सांसदोंसे जो आरोपी से उन्हें बचाना चाहते रहे हैं उन्हीं

मादा प्रछला दो सरकारो मध्यांतरा सन कवल परेझ करत रह ह वाले सरकार से पूछे जाने वाले सवालों को अवरुद्ध करते रहे हैं। किसी विवादास्पद विषय पर उहोंने न तो सिलसिलेवार जवाब दिये और न तथ्यात्मक जानकारी संसद के अंदर प्रस्तुत की। पिछली लोकसभा अंतिम दिनों में तो उहोंने रिकॉर्ड डेढ़ सौ से ज्यादा सांसदों का निलम्बन कराया और अपने कारोबारी मित्रों गौतम अदानी व मुकेश अम्बानी के साथ उनके रिश्तों को लेकर पूछे गये किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, मणिपुर की घटना हो या इलेक्ट्रोनिक वेटिंग मरीन अथवा इलेक्ट्रोरल बॉडस का मुद्दा, इनमें से किसी पर भी पर मोदी ने कभी संसद में विपक्ष के पूछे सवालों के जवाब नहीं दिये। उल्टे, इस बाबत हुई चर्चा में विपक्षी नेताओं के वक्तव्यों के बड़े हिस्सों को विलोपित किया गया था। अक्सर मोदी विरोधियों के सवालों के उत्तर सन्तुत के बाहर रैलियों व अ

ये बाजपेयी के नहीं मोदी के नेतृत्व की सरकार है

© राकेश अचल

अठारहवा लोकसभा में यद्यपि सरकार का पहली ही दिन विषयक के तेवरों का सामना करना पड़ा है और लेकिन विषयक को भी याद रखना चाहिए। विषयक 2024 में भाजपा के नेतृत्व में तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनी है और इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं। ये सरकार अटलबिहारी बाजपेयी की सरकार नहीं है जिसे आपानी से अपदस्थि किया जा सके। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी गठबंधन की सरकार में हालाँकि भाजपा के ताकत 2014 और 2019 जैसी नहीं है, लेकिन भाजपा की हैसियत अभी भी मरे हुए हाथी जितनी तो है ही, यानि कम से कम सवा लाख की इसलिए विषयक ये सपने देखना छोड़ दे कि इसके सरकार को फूंक मार कर उड़ाया या गिराया जा सकता है। वैसे भी 2024 में देश की जनता ने भाजपा और विषयक को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया है और भाजपा की ताकत कम कर उसे बैशाखनंदन बनने दिया है वही विषयक को ताकत देकर ये संकेत दिया है कि यदि उन्हें सत्ता तक पहुंचना है तो एकत्र बनाये रखते हुए अगले चुनाव तक काम करने पड़ेगा, हुलफुलाहट में विषयक यदि कोई कदम उठाता है तो वो देश के लिए भारी पड़ सकता है नयी संसद के पहले ही दिन विषयक ने संविधान के प्रतियां लेकर जो जुलूस निकला उससे नव्य सरकार भयभीत कदाचित नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने संसद में प्रवेश से पहले जिस तरीके से आपातकाल का पुण्य स्मरण किया है उससे जाहिर है कि न उनके सिर से कांग्रेस का भूत अभी उतरा है और न उनका देश को कांग्रेस विहीन करने का लक्ष्य ही बदला है। मोदी जी लंगड़ी-लूली सरकार के जरिये भी अपने पुराने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो सब करेंगे जो उन्होंने अपनी पिछली सरकारों में किया था। विषयक लाख संविधान के प्रतियां लहराए जो नयी सरकार के बढ़ते हुए कदमों को शायद नहीं रोक पायेगा। विषयक की ताकत का अंदाजा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वे चुनाव में ही हो जाएंगा।

नए जनादेश में सब कुछ स्पष्ट है। विषयक को विषयक की भूमिका में तब तक रहना है जब तक कि नाम आम चुनाव नहीं हो जाते। कायदे से चुनाव पांच साल बाद होना चाहिए लेकिन मौजूदा सूरतेहाल में ये चुनाव कभी भी हो सकते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि देश में नए चुनाव समय से पहले करने का फैसला विषयक नहीं, बल्कि मौजूदा सरकार ही करेगी। मौजूदा सरकार अगले कुछ ही महीनों में अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करने के लिए शीघ्र ही 'आपरेशन लोटस' की तज पर कोई नया आपेक्षण शुरू कर सकती है। नव्य



खिचड़ा सरकार के समन कल मा काग्रस और विषय निशाने पर था और आज भी है। सरकार सदन में अपने समर्थकों की मौजूदा संख्या बढ़ाने के लिए वो सब नैतिक -अनैतिक कर सकती है जो अटल बिहारी बाजपेयी नहीं कर पाए थे। अटल जी ने सत्ता बचने के लिए चिमटे का सहारा लेने से इंकार कर दिया था, लेकिन मोदी जी चिमटा क्या प्लास तक का इस्तेमाल करने से हिचकने वाले नहीं है। चूंकि नयी संसद का श्री गणेश कहें या विस्मिलात्त ह कहें, कड़वाहट के साथ हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी देश में अदावत की राजनीति का युग समाप्त होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में भी ईडी और सीबीआई विषय के खिलाफ उसी तरह इस्तेमाल की जाएगी जिस तरह पहले की गयी है। नयी सरकार ने भले ही सर्विधान की शपथ लेकर देश सेवा का वादा किया है किन्तु सर्विधान के दायरे में रहकर भी वो विषय को नुकसान करने से हिचकेगी नहीं। दरअसल अभी मध्य का छत्ता भाजपा के पास है। विषय के पास जो छत्ता है उसका मध्य निकाला जा चुका है या उसमें मध्य भरने में अभी समय लगेगा। ऐसे में विषय के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी एकता को बनाये रखने की है। सत्ता की चाशनी में विषय की कोई भी मछली छलांग लगा सकती है। देश के नए विषय को नहीं भूलना चाहिए कि देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर अभी भी संघ के प्रचारक काबिज है। यहां तक कि न्यायपालिका भी इससे अछूती नहीं है। अनेक मामलों में आये अदालती फैसलों पर आप संघ प्रचारकों की सोच की छाप परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पड़ती देख सकते हैं। आज भी पुरानी ईडी है जो अधीनस्थ न्यायलय से जमानत मिलने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आये देने के लिए ऊपर की अदालत

चित्रकूट संदेश

डीएम ने की पचास लाख से अधिक लागत के कार्यों की समीक्षा

स्वास्थ्य-पुलिस विभाग के कार्य समय से न करने पर ब्लैक लिस्ट करने की धमकी

सीएडीएस एक्सईन की गैरहाजिरी पर कारण बताओ नोटिस

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट जिलाधिकारी अधिकारी आनंद ने पचास लाख से ज्यादा के नियम कार्यों बाबत कार्यदायी संस्थाओं यूपीपीसीएल, आवास विकास परिषद बांदा, बन विभाग, उप्र सिडको, उप्र पुलिस आवास निगम, लोनिवि प्रांतीय खंड, लोनिवि नियम खंड बांदा, राज्य सेतु निगम, सीएडीएस जल निगम यूनिट बांदा, सीएडीएस यूनिट बाराणसी आदि को निर्देश दिये कि शासन



बैठक में निर्देश दें डीएम।

से टाइमलाइन अनुसार कार्य करायें।

मंगलवार को बैठक की अधिक्षता करते हुए डीएम अधिकारी आनंद ने अंतर्राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोलेन गेट व प्रकाश व्यवस्था कार्य प्रगति बाबत अधिकारी अधिकारी प्रांतीय खंड को निर्देश दिये कि अपूर्ण कार्य जल्द पूरे करायें। वहाँ

से मंगलवार हटाकर सफाई कराकर ब्रेक हटायें। जिले में बन रहे सर्किट हाउस निर्माण प्रगति बाबत नोटिस एक्सईन को निर्देश दिये कि बिजली फर्नीचर का स्टीमेंट शासन को भेजें, ताकि मंजुरी मिलें ही जल्द कार्य समय से न कराने पर ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दी। कार्यदायी संस्था व ठेकेदार पर मामला दर्ज करने की चेतावनी दी। कहा कि प्रोजेक्ट

फोटोग्राफ समेत अपलोड करायें। एक्सईन सीएडीएस के गैरहाजिर होने पर कारापान बताओ नोटिस जारी करने दिये। स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग के कार्य समय से न कराने पर ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दी। कार्यदायी संस्था व प्रकाश व्यवस्था कार्य प्रगति बाबत अधिकारी अधिकारी प्रांतीय खंड को निर्देश दिये कि अपूर्ण कार्य जल्द पूरे करायें। वहाँ

से टाइमलाइन अनुसार कार्य करायें।

मंगलवार को बैठक की अधिक्षता करते हुए डीएम अधिकारी आनंद ने घर में धुक्काड छेड़ाड का पॉक्ट विकास पुत्र प्रहलाद देवारी को गिरफतार किया। टीम में दोरोगा राजेन्द्र साप्ताह व प्रसाद व धर्मांशु यामिल रहे। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ अजीत कुमार पाण्डेय की अगुवाई में दोरोगा इन्द्रजीत गौतम ने आत्महत्या को प्रतिरिक्षण करने वाले वांछित/नामजद रंगीलाल निषाद पुत्र द्वारा प्रसाद निषाद करने वाले यामजद भजरा पदवाओं के गिरफतार किया। ज्ञात है कि इसकी छेड़ाड की हरकतों से तंग आकर रविवार की स्थान छह बजे नाबालिंग बालिका ने आत्महत्या कर ली थी। टीम में दोरोगा इन्द्रजीत गौतम, सिपाही राहुल पाण्डेय शामिल रहे।

पुलिस गिरफत में आरोपी।

पुलिस ग

